Estimation of Poverty

1041. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the States which do not have vibrant Panchayati Raj and have failed to pay minimum wages for agricultural workers have been put above the poverty line as per the NSS 50th round (1993-94) on the estimation of poverty; and

(b) if so, what are the facts which led the Planning Commission to come to this conclusion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) The Planning Commission estimates the incidence of poverty for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for all population from the quinquennial survey on consumer expenditure conducted by National Sample Survey Organisation (NSSO). The persons and not the states with consumption expenditure below the poverty line are counted as poor.

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

1042. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के उन नौ जिलों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान पर्वतीय क्षेत्र (उत्तराखण्ड) विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा उनमें से प्रत्येक परियोजना का नाम क्या है;

(ख) क्या इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास संबंधित कुछ प्रस्ताव योजना आयोग के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत उपरोक्त क्षेत्र की केन्द्रीय सहायता हिमाचल प्रदेश के समान करने का विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०ए०डी०पी०) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमौली तथा उत्तरकाशी जिलों के लिए दी जाती है। राज्य सरकार को सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रकीय तथा स्थानिक वितरण भी किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है जबकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी का राज्य है और केन्द्रीय सहायता के वितरण में इसे उपयुक्त महत्व दिया जाता है। तथापि, राज्य सरकार से तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने के विगत में प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 7.93 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती रही है। इसके अलावा, वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी और ऋषिकेश, बद्रीनाथ मार्ग के सुधार के लिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

Definition of "Poverty Line"

1043. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even Roti, Kapra aur Makan (Food, Clothing and a roof over-head) are universally accepted as the three basic needs of a man for civic-existence, the poverty-line continues to be defined in terms of caloric-value of food consumed, without any reference to clothes and abode;